अमृत वाणी

गरीबों के समान विनम्र अमीर और अमीरों के समान उदार गरीब ईश्वर के प्रिय पात्र होते हैं।

-शेख सादी,

सलमान को 5 वर्ष की सजा

राजस्थान में जोधपुर की स्थानीय अदालत ने बहुचर्चित काकाणी हिरण शिकार मामले में सलमान खान को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत का यह फैसला लगभग 20 वर्ष बाद आया है। चूंकि सलमान की यह सजा 3 वर्ष से अधिक की है इसलिए उन्हें तत्काल जमानत मिलना संभव नहीं था अत: एक रात उन्हें जोधपुर के जेल में बीतानी पड़ी।

सलमान का जेल जाना केवल उनके स्वयं, उनके परिवार या मित्रों के लिए ही बहुत बड़ा आघात नहीं है, फिल्म, टेलीविजन शो और एड वर्ल्ड के कई प्रोजेक्टों के लिए भी भारी नुकसान का मामला है फिर भी इतने बड़े फिल्मी सितारे के खिलाफ अदालत के इस फैसले ने यह सिद्ध कर दिया कि कानून के आगे सब बराबर हैं और अन्याय की सजा मिलती ही है, चाहे आज हो अथवा दस वर्ष बाद।

सलमान को जिस कांकाणी हिरण का शिकार करने के मामले में यह सजा मिली है वह एक दुर्लभ प्रजाति का हिरण है। वैसे ही हमारे देश में शिकार प्रतिबंधित है। उस पर ऐसे किसी जानवर जो दुर्लभ हो को मारना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इसीलिए अदालत ने उन्हें वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम की धारा 9/51 के तहत दोषी माना है। बताया जाता है कि इस प्रकरण में जिन्होंने सलमान के खिलाफ गवाही दी वे अंत तक टस से मस नहीं हुए जिसकी कीमत सलमान को चुकानी पड़ी।

दरअसल कुछ बड़े लोग अपना शौक पूरा करते समय नतीजों की चिन्ता नहीं करते लेकिन जब उसकी कीमत चुकानी पड़ती है तब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। वैसे भी मानवीयता के तौर पर बेजुबान जानवरों की हत्या करना अत्यंत मार्मिक है। ऐसा करने पर कानूनी रूप से रोक हो या न हो अपने विवेक से ही नहीं होनी चाहिए। यह तो इस प्रकरण के सह आरोपियों की अच्छी किस्मत है जो उन्हे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। अन्यथा सैफ अली खान, दुष्यंत सिंह, तब्बू, नीलम और सोनाली बेन्द्रे को भी आज सलाखों के पीछे रहना होता।

आए दिन कतिपय बड़े लोगों अथवा सेलीब्रिटीज व उनके परिवार जनों द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाने और सड़कों पर मासूमों को कुचले जाने की घटनाएं प्रकाश में आती है। हालांकि ज्यादातर मामले को किसी तरह दबा दिया जाता है मगर जब किसी को सजा मिलती है तब जाकर उन्हें एहसास होता है कि दूसरों को कष्ट देना क्या होता है।

सलमान के लिए उनके हर चहेतों को दुख तो है पर अगर कानून के मद्देनजर देखा जाय तो उन्हें पृथक कैसे किया जा सकता है।

स्वास्थ्य ही अनमोल धन है

विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। दुनिया भर में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरुक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है । अच्छी सेहत ही सबसे बड़ा धन है इसी विषय को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष स्वास्थ्य सब के लिए विषय पर फोकस किया है।

जीवन में स्वास्थ्य ही अनमोल धन है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन के विभिन्न क्षेत्रो में सफलता अर्जित कर सकते है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। व्यक्ति की सबसे बड़ी दौलत उसका शरीर और उसका स्वास्थ्य होता है। जीवन में स्वास्थ्य का मूल्य समझ कर ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए।

भारत में आम तौर पर लोगों में स्वास्थ्य चेतना का अभाव है। शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति भी लोग तभी चिंतित होते हैं जब कोई रोग उन्हें घेर लेता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि निष्क्रियता कई गंभीर बीमारियों को जन्म देती है। विश्व लगातार बढ़ रही निष्क्रियता नामक महामारी का शिकार हो रहा है आरामदेह जीवनशैली से जुड़ी बीमारियाँ, जैसे हृदय रोग और डायबीटीज, अब तक संपन्न देशों की बीमारियाँ मानी जाती थीं लेकिन अब विकासशील देश भी अब इसके शिकार हो रहे हैं । विश्व भर में इन बीमारियों से हर वर्ष दो करोड़ लोगों की मौत होती है और इनमें से अस्सी प्रतिशत गरीब देशों से हैं। इस तरह की बीमारियाँ दौड़-भाग से रोकी जा सकती हैं ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि विश्व के पचासी प्रतिशत लोग निष्क्रिय जीवनशैली बिता रहे हैं और विश्व के दो-तिहाई बच्चे भी पूरी तरह से सक्रिय नहीं हैं और इससे उनके भविष्य पर भी बुरा असर पड़ेगा। संगठन का कहना है कि साधारण व्यायाम जैसे पैदल चलना, नृत्य करना और यहाँ तक की सीढ़ियाँ चढ़ना भी सेहत को ठीक रख सकता है । शोध बताते हैं कि खानपान में साधारण परिवर्तन और हल्के व्यायामों से आंतों के कैंसर के खतरे को सत्तर प्रतिशत और डायबिटीज को साठ प्रतिशत कम किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना ही मानव स्वास्थ्य की परिभाषा है । भारत ने पिछले कुछ सालों में तेजी के साथ आर्थिक विकास किया है, लेकिन इस विकास के बावजूद बड़ी संख्या में लोग कुपोषण के शिकार हैं जो भारत के स्वास्थ्य के प्रति चिंता उत्पन्न करता है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार तीन साल की अवस्था वाले 3.88 प्रतिशत बच्चों का विकास अपनी उम्र के हिसाब से नहीं हो सका है और 46 प्रतिशत बच्चे अपनी अवस्था की तुलना में कम वजन के हैं, जबकि 79.2 प्रतिशत बच्चे एनीमिया (रक्ताल्पता) से पीड़ित हैं। गर्भवती महिलाओं में एनीमिया 50 से 58 प्रतिशत बढ़ा है। पिछले कुछ सालों में हमारे देश में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का प्रभाव बढ़ा है साथ ही डायबिटीज, हृदय रोग, क्षय रोग, मोटापा, तनाव की चपेट में भी लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। महिलाओं में स्तन कैंसर, गर्भाशय कैंसर का खतरा बढ़ा है। ये बीमारियां बड़ी तादाद में उनकी मौत का कारण बन रही हैं। ग्रामीण तबके में देश की अधिकतर आबादी उचित खानपान के अभाव में कुपोषण की शिकार है। महिलाओं, बच्चों में कुपोषण का स्तर अधिक देखा गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रति 10 में से सात बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं। वहीं, महिलाओं की 36 प्रतिशत आबादी कुपोषण की शिकार है।

स्वास्थ्य सिर्फ रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली की स्थिति है। स्वस्थ लोग रोजमर्रा की गतिविधियों से निपटने के लिए और किसी भी परिवेश के मुताबिक अपना अनुकूलन करने में सक्षम होते हैं। रोग की अनुपस्थिति एक वांछनीय स्थिति है लेकिन यह स्वास्थ्य को पूर्णतया परिभाषित नहीं करता है। यह स्वास्थ्य के लिए एक कसौटी नहीं है और इसे अकेले स्वास्थ्य निर्माण के लिए पर्याप्त भी नहीं माना जा सकता है। लेकिन स्वस्थ होने का वास्तविक अर्थ अपने आप पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीवन जीने के स्वस्थ तरीकों को अपनाया जाना है।

बाल मुकुंद ओझा
(ये लेखक के अपने विचार है)

सत्ता, पद, धन के पीछे संत महंत विद्यमान क्या-क्या नहीं करते

हा एक समय राजा, धनपति संत.महंत के पास जाकर याचना करते थे और सलाह.मशवरा लेते थे। कारण संत महंत संसार से वैराग्य भाव से अलग होकर अपना कल्याण करते हैं। प्रथम और उसके बाद समाज का अन्न, सुख सुविधाएँ पाने के कारण समाज को वो उपदेश। प्रवचन से अनुग्रहित करते हैं। वैसे राजा या मुख्यमंत्री को अपने मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए। जैसे भाई, साला, गुरु, दामाद जो राजा के विशेष कृपा पात्र होने पर राजा अपनी नाराजगी व्यक्त नहीं कर सकता और वो राजा की आड़ में जनता को अधिक कष्ट और धनार्जन में लाभ उठाते है और अधिकारी कर्मचारियों पर अत्याचार भी करते हैं।

जो संत.महंत राजा की कृपा पर जीते हैं वे एक प्रकार से पराधीन, गुलाम और चापलूसों की श्रेणी में आते है और जैसे भेड़ को राजा का आश्रय मिल जाता हैं वो शेर बन जाता हैं। कमजोर भी बलवान हो जाता हैं। जो राजा से अपमानित होता हैं वह सब जगह अपमान प्राप्त करता हैं। सत्ता सुख, पेट, आजीविका के लिए कौन.कौन क्या क्या नहीं करता चाहे अभिनेता, नेताए पढ़ा लिखाए वैश्याए संत महंत सब एक.दूसरे की खुशामद करते हैं।

दु:ख इस बात का हो रहा हैं जिन संतों को सरकार ने राजयमंत्री का पद देकर अपने को गौरवान्वित किया हैं या उन संतो ने राज्याश्रय पाने सरकार के सामने झुककर अपनी प्रतिष्ठा को गिराया हैं। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया हैं के साधु न होकर स्वादु हो गए। ये सब ढोंगी साधु हैं न जिनका कोई स्थान समाज में नहीं मात्र भीड़तंत्र का सहारा लेकर और सरकार से गुप्त समझौता कर उपकृत किया गया हैं। ये पहले सरकार की आलोचना कर रहे थे कि नर्मदा यात्रा में कितने अरबों रूपए का घोटाला किया गया हैं और वृक्षारोपण के नाम पर लूट मचाई गयी और पद का लोभ दिया तो वे अपनी बात से पलट गए। ये कैसे साधु जो कोई नियमों व्रतों का पालन नहीं कर सकते, मात्र राजा की वंदना कर उनके सामने नतमस्तक होगये और पद पाने के अलगा अलग तर्क रहे और हैं पर वास्तविकता ये पदलोलुपता से परिपूर्ण। संत का पद ,सत्ता सुख ,वैभव से क्या लेना देना घ्यदि इतनी ही लालसा है तो साधु का चोला छोड़कर सामान्य नागरिक बनकर चुनाव लड़े। ये तो ऊपर से थोपे गए तथा कथित नेता कहा जाये। इसीलिए साधु समाज कलंकित हो रही हैं। एक बार जब रावण मृत्यु शैय्या पर थे और उन्होंने भगवान् शिव को आह्वान किया की मेने आपकी खूब तपस्या ,पूजा पाठ किया और आपने युध्य में मेरा साथ नहीं दिया। तब शिवजी बोले रावण तुमने सीता का अपहरण साधु के रूप में छल कर किया जिससे साधु समाज कलंकित हुई। यदि तुमने सीताका अपहरण राजा के रूप में किया होता तो मैं साथ देता। ये साधु साधु न होकर सत्ता के पिठ्ठु हो गए। जो कल तक शिवराज सरकार की पोल खोलने वाले थे आज उनकी काक वंदना करने लगे। कैसा उज्ज्वल चरित्र हैं हमारे संतों का और मुख्य मंत्री का। क्या चुनाव जीतने जितने भी निम्न हथकंडे अपनाना पड़ रहे हैं कर रहे हैं फिर अपने भाषणों और प्रवचनों में क्यों धरम और नैतिकता की शिक्षा देते हैं घ्यह बहरुपियापन हैं।

इस बार शिवराज सिंह कितनी ही लोभ, घोषणा और लाभ दे पर जनता क भरम टूट चूका हैं। अहंवाद या फिर सत्ताशीन अधिक समय तक होने से और भरे पेट होने से जो शासन की पकड़ होना चाहिए थी वह खतम हो चुकी। जो राजा प्रसन्न होने पर किसी को पुरुस्कार न दे सके और कुपित होने पर दंड न दे सके वह तीसरे श्रेणी का माना जाता हैं। सेवानिवृति उम्र बढ़ाने, और नौकरियों की भारती करने से अब कोई खुश नहीं होने वाला। ये सरकार बेरोजगारों से कमाई कर अपना रोजगार बना रही। थोड़ी पोस्ट और अधिकतम आवेदन और उनकी कमाई से अपने सुख। संतों की नियुक्ति से क्या सरकार अधिक धार्मिक हो जाएँगी। ये सब रंगे सियार हैं, इनका चोला एक पानी की डुबकी में घुल जाएगा। इनकी कोई भी उपयोगिता समाज और शासन में नहीं हैं। ये परोक्ष में जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं और फिर सफाई में धरम की आड़ लेते हैं या भीड़तंत्र काउपयोग करते हैं। इस पर पुर्नविचार करे। शिवराज तुम्हारा छल अधिक नहीं चल पायेगा

कितने संतो महंतों मठधीशों और साधुओं की चरण वंदना करोगे

सुनो एक बात बहुत महत्वपूर्ण हैं जब तक मनसा, वचन और कर्मणा में एकाकार नहीं होगा तब तक हालत ऐसी होंगी की गधे की पीठ पर सोना लादो या मिटटी मक्का गए मदीना गए बनकर आये हाजी, न आदत गयी न इल्लत गयी रहे पाजी के पाजी ये सब संत महंत बहुत निराले हैं ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ जैसे नेता, मंत्री होते हैं वैसे ही होते हैं मठाधीश।

डॉ. अरविन्द जैन
(ये लेखक के अपने विचार है)

नक्सलवाद गलतफहमियां न पालें

केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों दावा किया है कि देश में नक्सलवाद की गंभीर चुनौती अब खत्म होने की कगार पर है। यह इससे स्पष्ट है कि अब माओवादी सुरक्षाबलों के खिलाफ कायराना हमलों का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि वे सीधे.सीधे मुकाबला करने में सक्षम नहीं हैं। पिछले दिनों देश में नक्सल विरोधी अभियानों का नेतृत्व करने वाले केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 79 वें स्थापना दिवस पर गृहमंत्री ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ इन बलों के अभियानों के कारण हाल के दिनों में माओवादियों की घटनाओं में भारी कमी आई है और नक्सलियों के हताहत होने की संख्या बढ़ी है। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि यह बात सच होने के बावजूद आश्वस्तिदायक नहीं है। यह सच है कि नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण की घटनाएं भी बढ़ी हैं। लेकिन यह भी सच है कि नक्सली अब भी हिंसक वारदातें कर रहे हैं और सुरक्षा बलों के लोग मारे जा रहे हैं।

यह कैसे भुलाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने सुरक्षा बल के नौ जवानों को शहीद कर दिया था। जवानों की माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल नक्सलियों के बिछाए बारूदी सुरंग की चपेट में आ गई थी, जिसमें विस्फोट होने से ये जवान शहीद हो गए थे।

माओवाद अब गंभीर चुनौती बना हुआ है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क निर्माण कार्य के दौरान सीआरपीएफ जवानों की मौत का हवाला देते हुए गृहमंत्री का कहना है कि देश में नक्सलवाद की समस्या अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है और लोग अच्छी तरह यह समझने लगे हैं कि नक्सली गरीब विरोधी, आदिवासी विरोधी और विकास विरोधी हैं। सरकार के दावों के बावजूद छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक बार फिर एक आइइडी में हुए विस्फोट में जिला रिजर्व गार्ड ;डीआरजीद्ध के चार जवान घायल हो गए। विस्फोट फुलबागड़ी पुलिस थाना क्षेत्र में सिरसेत्ती गांव के पास एक जंगल में हुआ, जब सुरक्षाकर्मी एक नक्सलरोधी अभियान चला रहे थे। डीआरजी प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा है। नक्सलवादियों को अब भी यह विश्वास है कि वे हिंसा के बूते देश में क्रान्ति ला सकते हैं। लेकिन हम मानते हैं कि ऐसी हिंसा से कुछ समय के लिए कुछ विशिष्ट प्रभावित क्षेत्रों उत्तेजना, तनाव अव्यवस्था, आतंक और अराजकता जैसी स्थिति बन सकती है। लेकिन इससे देश का निजाम बदलना मुमकिन नहीं है। फिर नक्सलियों ने जिस तरह धनसंग्रह के लिए वसूली का जो सिलसिला चला रखा है उससे उनके भटकाव का पता चलता है। हमारा मानना है कि सरकार और नक्सली दोनों ही गलतफमियाँ पाले हुए हैं। और गलतफहमियों का शिकार कोई समूह निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सरकार और नक्सलियों को गलतफमियों को दूर कर वास्तविकताओं को समझें और मिलकर स्थायी शांति स्थापित करने की राह निकालें।

अजित वर्मा
(ये लेखक के अपने विचार है)

राजकाज

भारतीयों की मौत और बयान

इराक में मारे गए 39 भारतियों के अवशेष परिजनों को सौंपने के बाद विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह ने मीडिया को बताया कि सभी 40 भारतीय अवैध तरीके से इराक गए थे, इसलिए दूतावास के पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। गौरतलब है कि अवैध ट्रैवल एजेंट के माध्यम से ज्यादातर लोग विदेशों में घूमने और नौकरी करने चले जाते हैं, जिसकी जानकारी विदेश दूतावास के पास नहीं होती है। इसलिए मोदी सरकार ने 2014 में एक अभियान चलाया था जिससे अवैध एजेंट के जरिए कोई विदेश न जाने पाए। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करने की बात भी सामने आई है, लेकिन यहां बात इराक में मारे गए 39 भारतीयों की है, जो अब खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं और सदमें में उनके परिजन भी बहुत कुछ कहने और सुनने की स्थिति में नहीं होते हैं। ऐसे में इस तरह की सच्चाई बयान करना और फिर पूरी जिम्मेदारी अवैध एजेंट और मृतकों पर डाल देना क्या उचित प्रतीत होता है।

पाक के प्रति अमेरिकी रुख

पाकिस्तान में हाफिज सईद की राजनीतिक पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग यानी एमएमएल एक आतंकवादी संगठन है। यह बात हम नहीं कह रहे बल्कि ऐसा अमेरिका ने कहा है। वैसे भी एमएमएल मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के नेतृत्व वाले आतंकवादी संगठन जमात.उद दावा का ही राजनीतिक मोर्चा है। इस कारण अमेरिका ने जहां एमएमएल को आतंकवादी समूहों की सूची में शामिल किया वहीं उसने तहरीक.ए.आजादी.ए.कश्मीर यानी टीएजेके को भी आतंकवादी घोषित कर दिया है। इससे यह तो तय हो गया कि अमेरिका पाकिस्तान की सरकार से खासी नाराज हैए इसलिए उस पर लगातार शिकंजा कसने का काम कर रहा हैए लेकिन जानकारों की मानें तो यह दिखावे की कार्रवाई है, क्योंकि अमेरिका का मकसद पाकिस्तान को चीन से दूर करना है ताकि वह उसका इस्तेमाल अपने तरीके से करता रहे।

देश को तोड़-फोड़ की राजनीति कब तक बर्बाद करती रहेगी

आजादी के बाद देश में जब भी विरोध जतने की प्रक्रिया शुरू होती है, तोड़ . फोड़ की राजनीति शुरू हो जाती है जिसे देश में कार्यरत वोट बटोरने की राजनीति से प्रेरित राजनीतिक पार्टियां अपने स्वहित में इस तरह के आंदोलन को शांत करने के वजाय और उग्र बनाने की दिशा में सक्रिय हो उठती है जिससे इस तरह के आंदोलन को भडकाने में और ज्यादा शह मिलने लगती है। इस तरह के आंदोलन में शामिल वास्तविकता से काफी दूर खड़ी भीड़ अपने ही देश को बर्बादी के कगार पर पहुंचाने में मददगार होती है। इस तरह के हालात में शामिल लोग भूल जाते है कि यह देश अपना है, जो हम आंदोलन से देश को नुकसान पहुंचा रहे है उसकी भरपाई भी हम सभी को ही करनी है। राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासत रोटियां इस तरह के आंदोलन की आड़ में सेकती चली जा रही है और देश इस तरह के आंदोलन से ग्रसित होकर दिन पर दिन बर्बाद होता जा रहा है। इस तरह के आंदोलन में काश्मीर के अन्दर पत्थर बाज हो , सीमा पर आतंकवाद को शह देते अपने लोग हो, नक्सलवाद की उभरती तस्वीर हो या देश में होते धार्मिक उन्माद हो, सभी को समर्थन राजनीतिक दलों के द्वारा यहां मिल रहा है जिससे समस्यायं और उलझती जा रही है। देश में तोड़ . फोड़ की राजनीति से जुड़ी आंदोलन की राह राष्ट्रहित में कदापि नहीं हो सकती।

देश आज गुलाम नहीं सवतंत्र है जहां भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिक सर्वोपरि मानी गई है। जब किसी को भी कहीं सहारा नहीं मिलता वह न्यायपालिका का दरवाजा खटखाता है और उसे वहां से न्याय मिलने की पूरी आश रहती है। न्यायपालिका भी राष्ट्रहित में निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र है। अभी हाल ही में 20 मार्च 18 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जातिध्जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत किये गये संशोधन जहां तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने एवं अग्रिम जमानत को मंजूरी दिये जाने को लेकर दलित संगठनों ने भारत बंद का आगाज किया जिसका खुला तांडव देश भर में देखने को मिला। इस प्रसंग से जुड़े आंदोलनकारी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा सहित देश के अन्य भागों में तोड़ . फोड़ करते रहे, आगजनी से लेकर हत्या तक की घटनाएं सामने उभर कर आई और देश की राजनीतिक पार्टिया आपनी . अपनी सियासत रोटियां सेंकने में मशगूल रही। इस तरह के हालात कभी भी देश के हित में नहीं हो सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने पुर्व अधिनियम में कुछ कमियां देखी होगी जिसके संशोधन पर विचार किया होगा। सर्वोच्च न्यायालय के इस संशोधन से सहमत न होने पर संबंधित संगठनों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात उठानी चाहिए थी जिससे देश को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे पर ऐसा बदली भारतीय आंदोलन की पृष्ठभूमि में कहीं से नजर नहीं आ रहा है।

आरक्षण का मुद्दा आये दिन ज्वलंत रूप धारण करता जा रहा है जिसकी आग में पूरा देश धू.धू कर जल रही है। जातिगत आधार पर आरक्षण का यह रूप देश के समक्ष विकराल रूप धारण कर देश की एकता, अखंडता, संप्रभूता को लीलने को तैयार बैठा है। पर इसे हटाने की आज कोई भी बात करे तो देश में तोड़ . फोड़ की राजनीति शुरू हो जायेगी। इस खेल में आज देश के सभी राजनीतिक दल शामिल होकर इसे भुनाने की प्रक्रिया में संलग्न होकर स्वहित की राजनीति कर रहे हैं। जहां आज प्रतिभा को भी चुनौती मिलने लगी है जिसके कारण देश की युवा पीढ़ी में भारी असंतोष फैलता जा रहा है। जिसे लेकर देश में आंदोलन का रूख बदलता जा रहा है। जो देशहित में कदापि नहीं। आरक्षण सभी को दे नहीं सकते जो आरक्षण ले रहे है, उनसे वापिस ले नहीं सकते भले उनके हालात पहले से काफी बेहतर हो चुके हो। यह हमारी देश की बिडम्बना ही है। जो नियम एक बार बन जाय उसके संशोधन पर बवाल मचने लगे। देश में राजनीतिक विरासत के तहत जगह . जगह दंगे . फसाद होते ही रहे है। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले, बिहार के औरंगाबाद, समसतीपुर में भड़के सांप्रदायिक हिंसा से देश में जो तनाव उभरता दिखाई दे रहा है, देश को किस मोड़ पर खड़ा करेगा घ् विचारणीय पहलू है।

देश में किसानों का आंदोलन हो, आरक्षण का आंदोलन हो या कोई और आंदोलन हो सभी के तहत तोड़ . फोड़ की राजनीति सक्रिय हो जाती है। जो राष्ट्रहित में कदापि नहीं। इस तरह के परिवेश पर मंथन होना चाहिए। देश अपना है , इसे किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे, इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुये आंदोलन की पृष्ठभूमि बनाई जानी चाहिए। आंदोलन की सही लोकतांत्रिक दिशा तय की जानी चाहिए। देश को कब तक आंदोलनीय पृष्ठभूमि के तहत तोड़-फोड़ की राजनीति बर्बाद करती रहेगी, विचार किया जाना चाहिए। जो राजनेता या राजनीतिक दल इस तरह की प्रक्रिया को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहा हो,उसपर तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। इस दिशा में तुष्टिकरण की नीति देश की एकता, संप्रभूता एवं अस्मिता को नुकसान पहुंचा सकती है।

डॉ. भरत मिश्र प्राची
(ये लेखक के अपने विचार है)